

नई सरकार भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्तों की नई इबादत लिखेगी

इमरान खान से भारतीय उच्चायुक्त करेंगे मुलाकात, आतंकवाद पर हो सकती है चर्चा: सूत्र

नई दिल्ली ।

पाकिस्तान के अगले संभावित प्रधानमंत्री इमरान खान से आज भारत के उच्चायुक्त त अजय बिसारिया और उप उच्चायुक्त जेपी सिंह से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में नई सरकार के गठन से पहले बिसारिया और जेपी सिंह की इमरान के साथ इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मुलाकात के

दौरान अजय आतंकवाद पर इमरान से चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्तों की नई इबादत लिखेगी। उल्लेखनीय है कि इमरान खान अब तक अमेरिका, रूस, ईरान, सऊदी अरब, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के राजनयिकों से मिल चुके हैं। अगर पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारने में गंभारता दिखाता है तो एक बार फिर से दोनों देशों के

रिश्ते पटरी पर लौट सकते हैं। बता दें कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में हुए चुनाव में इमरान को बहुमत मिला है और वे जल्द ही पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इमरान ने भारत के साथ बेहतरीन संबंधों की इच्छा भी जाहिर की थी। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए इमरान को जीत की बधाई देने के लिए फोन किया था।



संक्षिप्त समाचार



इस बार स्वतंत्रता दिवस होगा खास, पहली बार सुरक्षा होगी देश की बेटियों के हवाले

नई दिल्ली । स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय काफी सतर्क है। पीएम मोदी जब लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो इस दौरान उनकी सुरक्षा में जहां एसपीजी और लोकल पुलिस होगी वहीं इस बार दिल्ली पुलिस का विमिन स्क्वाट कमांडो का दस्ता भी वहां मौजूद रहेगा। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस स्पेशल विमन कमांडो को दिल्ली की जनता की सुरक्षा में तैनात करेंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस का यह कमांडो दस्ता देश की किसी भी स्टेट पुलिस में पहला दस्ता है। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की देखरेख में बनाए गए इस विशेष दस्ते में 36 विमन कॉन्स्टेबल हैं। इनको करीब 15 महीने तक सख्त ट्रेनिंग दी गई है। आमतौर पर कमांडो ट्रेनिंग 12 महीने की होती है लेकिन विमिन स्क्वाट कमांडो को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है जोकि मेल कमांडो से भी अधिक ट्रेंड है। इस दस्ते में असम से 13, मणिपुर से 5, अरुणाचल प्रदेश से 5, सिक्किम से 5, मेघालय से 4, नगालैंड से 2 और मिजोरम व त्रिपुरा से 1-1 कॉन्स्टेबल ली गई हैं। यह दस्ता बख्तरबंद गाड़ियों में तैनात होगा और इसे चलाएंगी भी विमन कमांडो ही। फिलहाल इस दस्ते को राजस्थान और विजय चौक पर तैनात किया जाएगा।

राफियाबाद में मुठभेड़ स्थल से मिला

हथियारों का जखीरा

श्रीनगर । उत्तर कश्मीर में बारामुला जिला के रफियाबाद क्षेत्र में सुरक्षाबलों द्वारा 8 अगस्त को किए गए एनकाउंटर में भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद हुआ है। इस दौरान पांच आतंकी मार गिराए गए थे। इस कार्रवाई के बाद वहां बड़े पैमाने पर सच ऑपरेशन चलाया जा रहा था। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों को कई राइफलें और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। मौडिया को शूकवार को जब्त किए गए हथियारों को दिखाया गया। बारामुला जिले के वनक्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की संख्या गुरुवार को पांच हो गई थी। पुलिस ने बताया कि रफियाबाद में दूनीवाड़ी जंगलों के आस-पास सुरक्षाबलों की गोलीबारी में गुरुवार सुबह पांचवें आतंकवादी की मौत हो गई। ब्रिगेडियर डी. आर. राय ने कहा कि इन हथियारों के जखियारों की जांच से पता चला कि ये आर्म्स आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के हो सकते हैं। इन आतंकियों ने संभवतः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से एलओसी पार कर घाटी में घुसे थे। क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद बुधवार सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस दौरान चार आतंकवादी ढेर हो गए और भारतीय सेना का एक पैरा कमांडो घायल हो गया था। मुठभेड़ आधिकारिक तौर पर गुरुवार को समाप्त हुई लेकिन क्षेत्र में लगातार सुरक्षाबलों की खोजबीन जारी रही। इसी दौरान बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर में आतंकी की किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। उत्तरी कश्मीर के बांडीपूरा जिले के गुरेज सेक्टर में सेना के एक बड़े ऑपरेशन में एक मेजर और सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए थे। इस कार्रवाई के बाद एल.ओ.सी. से सटे सीमा इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया उधर, बारामुला-उडी रोड पर एक आतंकवादी को ग्रेनेड के साथ अरेस्ट किया गया था। जांच में पता चला है कि वह अंसार गजवतुल हिंद का सदस्य था। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

दिल्ली विधानसभा में पास हुआ अंशु प्रकाश को हटाने का प्रस्ताव



नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को हटाने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल की चांदनी चौक से विधायक अल्ताफ लांबा ने रखा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन को बताया कि मुख्य सचिव ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल की होने वाली बैठक से पहले एक नोट भेजा है जिसमें कहा गया है कि राजधानी में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला ‘जल्दबाजी’ में लिया गया है। सिसोदिया ने यह बयान मुख्यमंत्री की सदन में उस घोषणा के बाद दिया जिसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में प्रकाश को तुरंत मुख्य सचिव पद से हटाने की मांग की गयी है। यह भी कहा गया है कि सरकार ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के फैसले को अवदूर 2015 में ही मंजूरी दे दी थी। इसके बावजूद इसके क्रियान्वयन में देरी की गयी जिसकी जांच की जानी जरूरी है।

कटुआ में कुछ रेस्त्राओं में वैश्यवृति का धंधा चलाए जाने का आरोप ,खिाकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप

कटुआ । शहर के वाई पांच के कुछ रेस्त्राओं पर वैश्यवृति का धंधा चलाने का आरोप लगाया हुए स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस व प्रशासन की कार्यप्रणाली को कोसते हुए साफ कर दिया कि अगर इस धंधे को रोकने के लिए पुलिस ने कोई प्रयास न किए तो वह सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे जिसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से पुलिस व प्रशासन की होगी। प्रदर्शनकारियों ने नारी शक्ति जागृति मंच की सुष्मा महाजन, सतीश कुमार ने कहा कि वे लोग इस वाई में वैश्यवृति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह धंधा पिछले दस सालों से धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां रेस्त्राओं ने अब सारी हद्दों को पार कर दिया है जबकि यहां पर अब पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। यहां आने वालों से पांच सौ रुपये से लेकर एक हजार तक की वसूली कर रहे हैं उन्होंने कहा कि रेस्त्राओं वाले साफ कह रहे हैं कि उनकी पुलिस के साथ साठगांठ है।



नई दिल्ली ।

देश के विभिन्न राज्यों में जाति के आधार पर आरक्षण में एकरूपता लाने की शक्रवार को राज्यसभा में

मांग की गई क्योंकि अलग-अलग प्रदेशों में जातियों की अलग-अलग सूचियां होने से लोग आरक्षण से वंचित हो जाते हैं। सदन में समाजवादी पार्टी के बिशंभर प्रसाद

निषाद के निजी संकल्प पर चर्चा के दौरान सभी दलों के सदस्यों ने यह मांग की। निषाद ने संकल्प पेश करते हुए कहा कि मल्लाह कहार, मछुआरे, गोडिया, केवट, धीमर, कश्यप, कोली जैसी अनेक जातियों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सूचियों में रखा गया है, इसके कारण कोई किसी राज्य में पिछड़ी जाति का तो कोई किसी राज्य में सामान्य वर्ग में तो कोई किसी राज्य में अनुसूचित जाति का तो कोई अनुसूचित जन जाति का

है,इसके कारण वह आरक्षण से वंचित हो जाता है और उसकी नौकरी चली जाती है। उन्होंने कहा कि वर्षों से देश भर में यह विसंगतियां चल रही हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को संशोधित कर इसे एक समान बनाया जाए। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राकेश सिन्हा, कांग्रेस के दिवजय सिंह, प्रदीप टम्टा और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ आदि ने भी विधेयक का समर्थन किया। कई सदस्यों ने निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने और खाली पदों को भरने की मांग की।

नीलाम हो गई दाऊद इब्राहिम की संपत्ति, लगाई गई कीमत

मुंबई ।।

शहर के एक ट्रस्ट ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एक संपत्ति नीलामी में 3.51 करोड़ रुपये की खरीदी है। चार मंजिला इमारत ‘मसुल्ला’ की नीलामी केन्द्रीय विदेश मंत्रालय ने तस्कर एवं बिदेश विनिमय ‘मैनीपुलेटर’ (संपत्ति जव्तगी) कानून के तहत कराई। संपत्ति का

79.43 लाख रुपए आरक्षित दाम रखा गया था और इसके लिए दो पक्षों ने बोलियां लगाईं। एसबीयूटी के अलावा दिल्ली के एक वकील भूपेंद्र भारद्वाज बोली लगाने वाले दूसरे पक्ष थे। भारद्वाज ने कहा, ‘‘मैंने एक करोड़ 91 लाख 43 हजार रुपए की बोली लगाई थी और सार्वजनिक नीलामी जीती थी। मैंने ‘ई बोली’ में भाग नहीं लिया जहां एसबीयूटी ने ज्यादा बोली लगाई।’’ किसी संपत्ति की नीलामी में तीन चरणों की प्रक्रिया होती है जिसमें सार्वजनिक नीलामी, ‘ई बिडिंग’ और सील बंद निविदाओं को खोलना शामिल है। एसबीयूटी के एक सूत्र के



अनुसार, ट्रस्ट ने ई निविदा चरण में 3.43 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी लेकिन अंतिम चरण में उसने 3.51 करोड़ रुपए में सीदा पक्का किया। नीलामी के बारे में पूछे जाने पर एसबीयूटी के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ ‘मसुल्ला’ इमारत रहने के लिए अयोग्य ठहराई गई है और यह

किरायेदारों तथा पदयात्रियों के जीवन पर गंभीर खतरा पैद करती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, हमने नीलामी में भाग लिया और हमारी इच्छाभरी बाजार पुर्निकवास परियोजना के तहत इमारत को फिर से विकसित करने के लिए इसे हासिल किया।’’

राष्ट्रपति के नाम की फर्जी चिट्ठी फेसबुक पर पोस्ट करना पड़ा महंगा, अमेरिका से लौटने पर गिरफ्तार

नई दिल्ली ।

अपने फेसबुक अकाउंट पर राष्ट्रपति से मिला एक फर्जी पत्र पोस्ट करने के आरोप में बेंगलुरु के एक प्रबंधन कॉलेज के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज होने के एक साल बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आज बताया कि आरोपी हरिकृष्ण मारम एक साल से अमेरिका में था और इसी महीने बेंगलुरु लौटा था। उसकी उम्र 45-50 के बीच है। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने उसे बुधवार को गिरफ्तार किया। पिछले

साल राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने पिछले साल शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद साइबर प्रकोष्ठ के उप निरीक्षक भानू प्रताप ने मामले की जांच की। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मारम ने राष्ट्रपति से मिले ‘प्रशंसा पत्र’ की एक कथित तस्वीर पोस्ट कर दावा किया था कि डिजिटल मार्केटिंग पर उसने जो किताब लिखी है उसके लिए उसे सरहाना मिली है। अधिकारी ने बताया कि पत्र फर्जी था और मारम ने शेखी बघारने तथा किताब को चर्चा में लाने के लिए पत्र पोस्ट किया था। मामला दर्ज होने के वक्त मारम



अमेरिका में था और उससे संपर्क किया गया लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ। आरोपी बेंगलुरु में एक प्रबंधन स्कूल चलाता है और उसने एमबीए और बी फार्मा कर रखा है। उसे कल शहर की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

संसद का मॉनसून सत्र समाप्त, राज्यसभा में पेश नहीं हुआ ट्रिपल तलाक बिल



नेशनल डेस्क ।

तीन तलाक से संबंधित विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति न बन पाने के कारण इसे आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश नहीं किया गया और इस तरह यह विधेयक फिर लटक गया। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था और सरकार इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ आज ही सदन में पेश करना चाहती थी। विधेयक सदन की

आज की कार्य सूची में भी शामिल था। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में गैर-सरकारी कामकाज के दौरान सदस्यों को सूचित किया कि सरकार और विपक्ष के बीच सहमति न बन पाने के कारण विधेयक को आज चर्चा के लिए पेश नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय की विवाहित महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017 को लोकसभा ने पारित कर दिया था और इसे गत जनवरी में राज्यसभा में पेश किया गया था लेकिन विपक्ष की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने इसे चर्चा और पारित कराने के लिए आगे नहीं बढ़ाया था। राज्यसभा में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय

जनतांत्रिक गठबंधन का बहुमत नहीं है, इसलिए विधेयक पारित कराने के लिए विपक्ष का समर्थन जरूरी है। विपक्ष की आपत्तियों को देखते हुये मंत्रिमंडल ने इस विधेयक में गुरुवार को तीन संशोधनों को मंजूरी दी थी और सरकार चाहती थी कि इसे आज राज्यसभा में पेश किया जाए।

क्या है तीन बदलाव
अब सिर्फ पांडिता या रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

समझौता होने पर केस वापिस लेने का प्रावधान है। आरोपी को जमानत सिर्फ मेजिस्ट्रेट ही दे सकता है। पुलिस से जमानत नहीं मिल

सकती है। तीस साल पहले राजीव गांधी सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिम महिलाओं को भत्ता दिवाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि आईपीसी की धारा 125 जो तलाकशुदा महिला को पति से भत्ते का हकदार बनाता है, मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। आज भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति वहीं है जो तीस साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना आया है की पहले शाहबानो थी अब सायरा बानो है।उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर

कर ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के चलन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

शाह ने बुलाई बैठक

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने तीन तलाक बिल पर रणनीति को लेकर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के दफ्तर में एक बैठक बुलाई है जिसमें शाह, अनंत कुमार के अलावा राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी, विजय गोयल, अर्जुन मेघवाल मौजूद हैं।

ट्रिपल तलाक पर शायरा बानो की कानूनी लड़ाई

10 अक्टूबर 2015 शायरा बानो को उनके पति ने चिट्ठी से तलाक दिया।

23 फरवरी 2016 शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए याचिका दायर की।

22 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ट्रिपल तलाक बिल को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को सम्बोधित करते हुए कहा कि तीन-तलाक के खिलाफ लड़ाई वाली मुस्लिम माताओं और बहनों के साथ पूरा हिन्दुस्तान खड़ा है। ट्रिपल तलाक के कानून बनने से जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, वहीं मुस्लिम बोंर्ड इसका विरोध कर रहा है।

10 अक्टूबर 2015 शायरा बानो को उनके पति ने चिट्ठी से तलाक दिया।

संपादकीय

उल्लेखनीय जीत

राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में राजग प्रत्याशी के रूप में जनता दल-यू के सांसद हरिवंश की जीत इसलिए कहीं अधिक उल्लेखनीय है, क्योंकि एक तो उच्च सदन में बहुमत न होने के बाद भी सत्तापक्ष को विजय हासिल हुई और दूसरे करीब चार दशक बाद यह पद किसी गैर कांग्रेसी दल के खाते में गया। राजग का नेतृत्व कर रही भाजपा को यह जीत एक ऐसे समय मिली जब विपक्षी दल महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सत्तापक्ष के हरिवंश ने विपक्ष के बीके हरिप्रसाद को मात देकर यही रेखांकित किया कि कम से कम कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन का आकार लेना उतना सहज-सरल नहीं जितना आभास कराया जा रहा है। विपक्षी खेमों में सब कुछ ठीक नहीं, यह तभी प्रकट हो गया था जब महागठबंधन की पैरवी करने वाले दलों ने यह जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही डाल दी थी कि वह राज्यसभा उपसभापति के लिए अपने ही सदस्य को प्रत्याशी बनाए। इससे यही संकेत मिला कि वे या तो बीजे को लेकर सुनिश्चित नहीं थे या फिर कांग्रेस से निकटता बढ़ाते हुए नहीं दिखना चाह रहे थे। ध्यान रहे विपक्षी दलों में कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस विरोधी राजनीति की उजज हैं। चुनाव नतीजे से यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वैसी लामबंदी नहीं की जैसी जरूरी थी। उसकी रणनीति जो भी रही हो, उसे अपने रवैये को लेकर सवालों का सामना इसीलिए करना पड़ रहा है कि वह इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के प्रति गंभीर नहीं दिखी। दरअसल इसी कारण हरिप्रसाद के मुकाबले हरिवंश को कहीं ज्यादा वोट मिले। समझना कठिन है कि कांग्रेस ने कुछ विपक्षी और तटस्थ से दिख रहे दलों से संवाद-संपर्क क्यों नहीं किया? विपक्ष के विपरीत सत्तापक्ष का काम इसलिए आसान हो गया, क्योंकि अत्राद्रमुक और टीआरएस जैसे दलों के साथ बीजद भी उसके पाले में आ गया। इसी के साथ अभी कल तक और यहां तक कि अविश्वास प्रस्ताव के समय भाजपा से दूरी और नाराजगी जाहिर करने वाली शिवसेना ने हरिप्रसाद की हार सुनिश्चित की। अभी यह कहना कठिन है कि वह राजग का हिस्सा बनी रहेगी या नहीं, लेकिन यह संकेत तो मिला ही कि वह भाजपा के साथ अपने संबंधों को लेकर फिर से विचार कर रही है। 1यह अच्छा हुआ कि पत्रकार से सांसद बने हरिवंश के राज्यसभा उपसभापति निर्वाचित होते ही विपक्ष ने भी उन्हें बधाई दी। लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है। हरिवंश का राज्यसभा का उपसभापति बनना यह भी बताता है कि भाजपा और जद-यू का साथ और प्रगाढ़ हुआ है। भाजपा के घटक दल के किसी नेता को प्रतिष्ठित पद मिलने से गठबंधन धर्म को मजबूती मिलती हुई दिखी है। यह मजबूती भाजपा के नए सहयोगियों की तलाश सहायक बन सकती है। निन्संदेह लोकसभा चुनाव तक सत्तापक्ष और विपक्ष के समीकरणों में अभी और बदलाव होते रह सकते हैं, लेकिन अच्छा यह होगा कि राज्यसभा वरिष्ठों के सदन के रूप में ही नजर आए। उम्मीद है कि हरिवंश का पत्रकारिता का लंबा अनुभव राज्यसभा के काम-काज को और सुगम बनाने के साथ ही संवाद और सहयोग भाव को बल प्रदान करेगा।

आज का राशिफल

मे़ष	प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी या खोने की आशंका है।
वृषभ	व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। राजनैतिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। उदर विकार या लव्हा के रोग से पीड़ित रहेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आयेगी। प्रणय संबंध मधुर होंगे। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी।
मिथुन	जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आय और व्यय में संतुलन बना कर रहें। किसी अर्भज मित्र से मिलाप को संभावना है। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। खान-पान में संयम रहें। संतान के संबंध में चिंतित रहेंगे।
कर्क	प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुटुम्बजनों का सहयोग मिलेगा। धन हानि के योग हैं।
सिंह	जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्रोध व भावुकता में लिप्त नया निर्णय कष्टकारी होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
कन्या	आर्थिक योजना फलीभूत होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाणी की सोम्यता बनाये रहें। नए अनुबंध प्राप्त होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा।। व्यर्थ की भागवीट्ठ रहेगी।
तुला	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। काय्क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।
वृश्चिक	विश्वा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। वाणी की सोम्यता से व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगे। नए अनुबंध प्राप्त होंगे।
धनु	व्यावसायिक व पारिवारिक समन्याएँ रहेंगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है।
मकर	विश्वा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। मनोरंजन के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के योग हैं।
कुम्भ	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। किसी का वाणी के स्तर पर उद्दीप्त न करें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।
मीन	जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। धन, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

विचार मंथन

सलील त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार

बांग्लादेश के एक बड़े बुद्धिजीवी शाहिदुल आलम की गिरफ्तारी की वजह बनने वाले घटनाक्रम ने इस मुल्क के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है। एक, यहां रसूखदार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते और सबसे पहले आलोचकों को निशाने पर लेते हैं। दूसरा, आक्रोशित हो रहे छात्र इस मुल्क को आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर सकते हैं। और तीसरा, हुकूमत के बिना ही बांग्लादेश का कम-काज चल रहा है। छात्रों के आक्रोश की तात्कालिक वजह एक

दुखद सड़क दुर्घटना थी। जुलाई के अंत में कुछ छात्र ढाका में एक व्यस्त सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बस ने उन्हें कुचल दिया। इस दुर्घटना में दो छात्रों की मौत हो गई। सड़क सुरक्षा के मामले में बांग्लादेश का रिकॉर्ड काफी खराब है। शिपिंग, रोड व रेलवे सुरक्षा को लेकर बनी राष्ट्रीय कमेट्री के मुताबिक, पिछले वर्ष 7,397 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई, जबकि इस साल जून माह तक यह आंकड़ा 2,471 तक पहुंच चुका है। पुरानी गाड़ियां, बिना लाइसेंस की ड्राइविंग, गति सीमा का अन्देखी, खराब सड़क, भ्रष्टाचार और

सरकारी उदासीनता को दुर्घटनाओं का कारण माना जाता है। इस हादसे के बाद हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर गए, जिनमें से कई तो स्कूल यूनीफॉर्म में ही थे। सुरक्षित सड़क की मांग करते हुए वे गाड़ियों को रोकने लगे और ड्राइवरों के लाइसेंस व गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पेपर की जांच करने लगे। इस विरोध से सरकार में पेशानी पर बल पड़ने लगा। बाद में, ढाका के आस-पास कुछ ऐसे उरड़ जजीरा को दिए अपने इंटरव्यू में हथियार थे, तो कुछ मुक्ति आंदोलन का अपमान करते ‘क्या बांग्ला’ का नारा लगा रहे थे। जहा जाता है कि इनमें से

कई सत्तारूढ़ अवामी लीग की युवा इकाई छात्र लीग के समर्थक थे। नतीजातन, कई छात्रों से जमकर मारपीट हुई। पत्रकार सहित जो भी इस घटना वीडियो बना रहा था या फोटोग्राफी कर रहा था, उन सभी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके कैमरे आदि तोड़ दिए गए। पुलिस ने इस हिंसा को रोकने के लिए बहुत मामूली प्रयास किया। आलम भी इसी उद्देव का शिकार बने। बाद में डल जजीरा को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने तमाम घटनाक्रमों का सिलसिलेवार जिक्र किया व गैर-जिम्मेदाराना रवैये के लिए सरकार की

खुब लानत-मलामत की। इस इंटरव्यू के तुरंत बाद करीब 35 की संख्या में सुरक्षा बल सादे कपड़ों में उनके घर में दाखिल हुए और उन्हें साथ ले गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने क्लोज़-सर्किट कैमरा भी बंद कर दिया था। शुरु में चुप रही पुलिस ने बाद में बताया कि उन्हें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कानून की धारा ‘एस 57’ के तहत गिरफ्तार किया गया है। अगले दिन जबर आलम को अदालत में पेश किया गया, तो वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें न सिर्फ पीटा गया, बल्कि खून लगे कपड़े धोने के लिए भी मजबूर किया

गया। अदालत ने हालांकि उन्हें रिमांड पर भेज दिया, मगर मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और उन्हें अस्पताल ले जाने व गुरुवार तक उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा। मंगलवार की देर रात तक सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया था। बांग्लादेश में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि आलम के बहाने कट्टरपंथी खास संदेश देना चाह रहे हों, मगर बांग्लादेश के लोग अपनी आजादी को गंभीरता से लेते हैं। पिछले हफ्ते का घटनाक्रम बताता है कि बांग्लादेश 1971 के अपने आदर्शों से कितना दूर

चला गया है। मुक्ति आंदोलन के आखिरी दिनों में, पाकिस्तानी सेना ने नए मुल्क को हानि पहुंचाने के लिए दर्जनों नागरिकों और बुद्धिजीवियों को मार दिया था। ढाका के रेयर बाजार में उनकी याद में बने स्मारक पर असद चौधरी की एक पंक्ति है, जो आने वाली पीढ़ियों से एक प्रासंगिक सवाल पूछती है- तोमादेर जा बलार छिलो, बोलचे की ता बांग्लादेश? (जो आप कहना चाह रहे थे, क्या वह बांग्लादेश कहता है?) आज उन बलिदानियों के पास देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के लिए भी कई सवाल जरूर होंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

संपादकीय

बीमार का हाल नहीं अच्छा

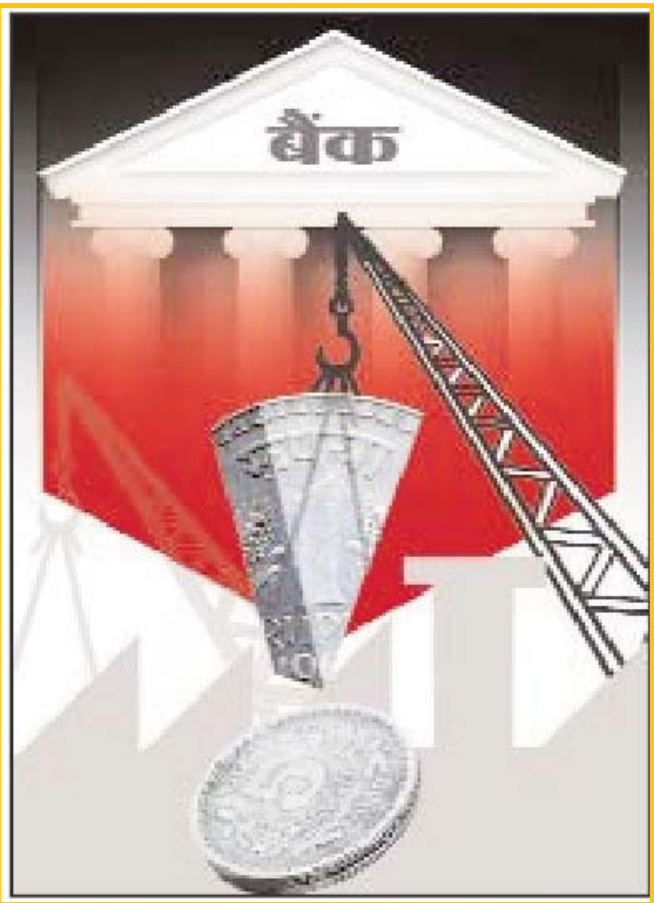
अर्थव्यवस्था/ अरविन्द मोहन

कुछ अजीब हो रहा है कि सारी चंचा या तो सीधे विकास की होती है, या फिर आर्थिक कामकाज के हर पक्ष की राजनीति की। आर्थिक मोर्चे पर कहीं से अच्छी खबर नहीं आ रही है, अमेरिका-चीन की टकराहट से पाइपलाइन बिछाने के बाद भी हमारे लिए ईरान से तेल लेना मुश्किल हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन अस्थिर है, रुपये की सांस फूल रही है, पर शेयर बाजार रोज नये रिकॉर्ड बना रहा है। जिस बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब है, उसके भी शेयर उछल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या एनसीआर में आर्थिक कामकाज की रफ्तार बढ़ना उससे जुड़ी सच्चाइयों पर चंचा नहीं कराता, बल्कि एक कंपनी द्वारा अपनी क्षमता का विस्तार करने की खबर के साथ एक ट्रिलियन डॉलर के निवेश और फिर उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश या स्वर्ग बनने की खबर ही आती है। चंचा नहीं होती कि जिस इलाके में न कोई खनिज है, न जमीन उद्योग लगाने लायक, न बाजार है वहां क्यों सबसे तेज आर्थिक विकास है। यह चंचा तो हमारा नेता वर्ग कभी नहीं करता कि एनसीआर न होता तो हिन्दी पट्टी के आर्थिक विकास का क्या होता क्योंकि कानपुर से लेकर रोहतास, ग्वालियर से रीवा-सतना तक के सारे पुराने कारखाने कहां गए, इसका हिसाब किसी एक पास नहीं है। खैर, सरकार, वित्त मंत्रालय और राजनेता भले चारों तरफ से आ रहें आर्थिक बेचेनी वाली खबरों का महत्त्व नहीं समझ रहे हों पर रिजर्व बैंक गंभीरता को समझ रहा है। तभी उसने मुद्रास्फीति की दरों में उठान देखकर भी लगातार दूसरी बार इंटर-बैंकिंग लेन देन के चार्ज बढ़ाए हैं। रिपो रेट बढ़ने का असर बैंकों की जमा दरों और ऋण की दरों पर दिखने लगा है, जो काफी समय बाद उठान पर हैं। बैंकों को पैसा अपने पास रखने के निर्देश भी हैं। एनपीए से परेशान बैंक अर्थव्यवस्था का बोझ उठाने के बजाय अर्थव्यवस्था पर बोझ बन गए हैं। खाताधारकों के लिए भी चिंता का कारण हैं। उनकी तरफ से बाजार में कम पूंजी आना नये निवेश के साथ उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री को भी प्रभावित करता है। एक जमाने में खासकर 2011 के बाद अर्थव्यवस्था में हाहाकार मचवाने में बैंकों द्वारा सूद की दरें न कम करने का योगदान भी था।बैंक तो हवा का रुख देखकर अपने खिड़की-दरवाजे बंद करने में जुट गए हैं पर सरकार और आर्थिक राजनय में इस बात की कोई चिंता नहीं दिखती। चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह की व्यावसायिक तनातनी है, उससे तेल की कीमतों से लेकर हर चीज में खतरा है। दक्षिण कोरिया की मोबाइल कंपनी भारत प्रेम और हमारे यहां व्यवसाय करने की आजादी से प्रेरित होकर नहीं आई है। इस बड़ी अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में पिस कर भागी हैं हमारा भी सिले-सिलाए वस्त्रों का कारोबार प्रभावित हुआ है। अभी तक हमारे लिए गनीमत यही है कि सोने और जवाहरात के हमारे आयात में कमी आई है। जवाहरात का काफी बड़ा हिस्सा गहनों में लगकर वापस निर्यात होता है पर सोना कम आना की महत्वपूर्ण है। लेकिन कुल विदेश व्यापार रिकॉर्ड घाटे की तरफ जा रहा है। पिछले महीने 27 महीने का सर्वाधिक घाटा रिकॉर्ड किया गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि लगातार सातवीं तिमाही में घाटा बढ़ेगा।जाहिरन विदेश व्यापार में घाटा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम आयात से बढ़ा है जबकि कीमतें अभी भी मनमोहन राज वाले स्तर तक नहीं गई हैं, बल्कि चालीस फीसद तक कम हैं। पर हम ईरान से सस्ता और सुविधाजनक तेल खरीदना इसलिए छोड़ रहे हैं कि अमेरिका ऐसा चाहता है।

अकेले तेल के खेल में ही गिरते रुपये की वजह से लाखों करोड़ का घाटा हो गया होगा। चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रु पये-डॉलर के खेल पर सचेत थे। उन्होंने कहा भी था कि डॉलर का मोल चालीस रु पये से ऊपर न जाने देंगे। पर जब डॉलर सत्तर को छू रहा है, तब मोदी या उनके मंत्री भूल से भी डॉलर का नाम नहीं लेते। अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा सूद की दरें बढ़ाना दुनिया भर से पूंजी को अमेरिका की तरफ आकर्षित करने का कारण बना है, तो चीन से व्यावसायिक तनातनी से दुनिया भर में डर का माहौल गहरा रहा है। डॉलर को सुरक्षित करेंसी मान कर भी उसमें निवेश हो रहा है। और मांग बढ़ने से डॉलर महंगा हुआ जा रहा है। कायदे से डॉलर की गिरावट से हमारे निर्यात को लाभ हो सकता था। पर ह्रीरे-जवाहरात की घटती मांग और सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में भी हम मात खा रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों पर नोटबंदी और जीएफटी की मार बहुत गलत समय में पड़ी। जब दुनिया का बाजार उभर रहा था, और हमारी अर्थव्यवस्था भी उत्साह में आ रही थी, तब इन दो फैसलों ने हमें कई कदम पीछे कर दिया। अब जीएफटी की वसूली तो व्यवस्थित होकर सरकारी राजस्व का हिसाब ठीक करने लगी

खाड़ी के देशों से भी अलग दर पर तेल मिलना बीते जमाने की बात हो चुकी है। तेल उत्पादन में भी हमारी अपनी भागीदारी पचास से गिरकर बीस फीसद से भी नीचे चली गई है, और कहीं चंचा नहीं होती। इसका पहला कारण तो यही है कि तेल आयात सरकार और सरकारी तेल कंपनियों के साथ ही हमारी निजी तेल कंपनियों के लिए कमाई का खेल बन गया है। कोई भी तेल की खपत घटाने, स्वदेशी तेल का हिस्सा बढ़ाने या तेल पर कर कम करने की बात नहीं करता। सो, तेल का खेल देश और उपभोक्ताओं के लिए भारी पड़ रहा है। एक मोटा अनुमान है कि तेल की कीमतें गिरने और उसका लाभ ग्राहकों तक न आने देकर सरकार हर साल पौने दो से दो लाख करोड़ रु पये का अतिरिक्त राजस्व वसूल रही है। फिर सरकार क्यों स्वदेशी उत्पादन और कम आयात की पैरवी करेगी। ऐसे में उच्चला या अन्य लोक-लुभावन कार्यक्रमों पर खर्चने की सहूलियत मिल जाती है।पर आर्थिक मामलों में सरकार के ही हाथ में सब कुछ नहीं है। होता तो वह जरूर डॉलर के मुकाबले रु पये की कीमत को थामने की कोशिश करती। डॉलर के रेट बढ़ने से उसे तेल की तरह का अप्रत्यक्ष लाभ नहीं हो रहा है। अकेले तेल के खेल में ही गिरते रुपये की वजह से लाखों करोड़ का घाटा हो गया होगा। चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रु पये-डॉलर के खेल पर सचेत थे। उन्होंने कहा भी था कि डॉलर का मोल चालीस रु पये से ऊपर न जाने देंगे। पर जब डॉलर सत्तर को छू रहा है, तब मोदी या उनके मंत्री भूल से भी डॉलर का नाम नहीं लेते। अमेरिकी फेडरल बैंक द्वारा सूद की दरें बढ़ाना दुनिया भर से पूंजी को अमेरिका की तरफ आकर्षित करने का कारण बना है, तो चीन से व्यावसायिक तनातनी से दुनिया भर में डर का माहौल गहरा रहा है। डॉलर को सुरक्षित करेंसी मान कर भी उसमें निवेश हो रहा है। और मांग बढ़ने से डॉलर महंगा हुआ जा रहा है। कायदे से डॉलर की गिरावट से हमारे निर्यात को लाभ हो सकता था। पर ह्रीरे-जवाहरात की घटती मांग और सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में भी हम मात खा रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों पर नोटबंदी और जीएफटी की मार बहुत गलत समय में पड़ी। जब दुनिया का बाजार उभर रहा था, और हमारी अर्थव्यवस्था भी उत्साह में आ रही थी, तब इन दो फैसलों ने हमें कई कदम पीछे कर दिया। अब जीएफटी की वसूली तो व्यवस्थित होकर सरकारी राजस्व का हिसाब ठीक करने लगी

है, पर एक निर्णायक वक्त पर उठे गलत कदम ने दीर्घकालिक नुकसान कर दिया है। अगर हमारे करखनिया उत्पादन का हाल ठीक होता तो शायद हम एक और उठान की तरफ बढ़ सकते थे क्योंकि बिजली, सड़क और संरचना क्षेत्र की सामान्य स्थिति ठीक है। पर मेक इन इंडिया और स्टार्टअप समेत सभी नई योजनाएं सिर्फ घोषणा के स्तर तक रही। बहुत आगे नहीं बढ़ी, बल्कि ले देकर खेती अलाभकर होने पर भी रोजगार देने से लेकर उत्पादन और अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। पर दिन ब दिन इसके अलाभकर होने से खेतिहर समाज परेशान है। और सरकार अगर सचमुच दो जमातों से डरती है, तो वह किसान और नौजवान ही हैं, जिन्होंने सालाना दो करोड़ रोजगार की उम्मीद में यह सरकार बनवाई थी।



परोपकार की उपेक्षित परंपरा

उदय प्रकाश अरोड़ा

एक के बाद एक अध्ययन और सर्वेक्षण भारत में असमान विकास को रेखांकित कर रहे हैं। ऐसे भी आंकड़े सामने आ रहे हैं कि गैर बराबरी के बीच भारत में अति अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान में इस अपने देश में कुल 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जहां भारत की गिनती उन देशों में होती है जहां बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है वहीं अमेरिका और चीन के बाद अरबपतियों की सबसे अधिक संख्या भारत में बताई जाती है। यदि यह वर्ग निर्धनता निवारण में हाथ बंटाए तो गरीबी कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन भारत में बिल गेट्स जैसे अरबपति कम ही हैं। अपने देश में ऐसी खबरें आती ही रहती हैं कि अमुक अरबपति ने बेटे या बेटी की शादी में करोड़ों रुपये खर्च किए। इस तरह की खबरें भी आम हैं कि धार्मिक स्थल विशेष में चंदे का रिकार्ड कायम हुआ। कुछ बड़े धार्मिक स्थलों में हर वर्ष चंदे की राशि पिछले रिकार्ड को पार करती है। यह सैकड़ों करोड़ रुपये में होती है। धर्म स्थलों के निर्माण में भी लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं। हाल में गुजरात में पाटीदार समुदाय के लोगों ने एक मंदिर परिसर के निर्माण के लिए केवल तीन घंटे में डेढ़ सौ रुपये एकत्र किए। लक्ष्य सौ करोड़ रुपये का ही था। यह वही समुदाय है जो कुछ समय पहले आरक्षण की मांग को लेकर चर्चा में था। धार्मिक स्थलों के निर्माण के साथ-साथ

लोग ऐसे स्थलों में दान करने में भी उदारता दिखाते हैं। इस मामले में भारत के मुकाबले पश्चिम की स्थिति भिन्न नजर आती है। हाल तक दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्ति के तौर पर चर्चित बिल गेट्स ने पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ मिलकर समाजसेवा के लिए एक कोष बनाया है। बिल एंड गेट्स फाउंडेशन वैज्ञानिक शोध के साथ समाज सेवा के लिए जमकर पैसा देता है। इस फाउंडेशन ने जानलेवा बीमारियों से बचाव और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किए हैं। बिल गेट्स ने अमेरिका के अरबपति कारोबारियों के साथ मिलकर ‘गिविंग प्लेज’ नामक जिस सोशायटी की स्थापना की थी उसके सदस्य यह शपथ लेते हैं कि वे अपनी संपत्ति का कम से कम आधा भाग सेवा कार्यों में व्यय करेंगे। निन्संदेह यह कहना गलत होगा कि पश्चिम की तरह का सेवा भाव अपने देश में नहीं है। दान और सेवा की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। उपर्युक्त-समय पर समाज के धनीवर्ग ने अपनी संपत्ति गरीबों के बीच बांटी हैं। आजादी के बाद से यह परंपरा लुप्त सी होती दिखाई पड़ती है। गांधी जी को पूंजीपतियों की सदाशयता पर पूर्ण विश्वास था। यह उनकी प्रेरणा की ही परिणाम था कि बिड़ला, बजाज और टाटा जैसे घराने आजादी की लड़ाई में अपनी तरह से सहयोग करते थे। उद्योगपति जमाना लाल बजाज के बारे में गांधी ने अपने हरिजन वार्ता में लिखा था, ‘‘मेरा कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने अपने शरीर, दिमाग और धन से पूरा सहयोग न दिया हो। गांधी जी को अंग्रेजों के

खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने में अनेक बार टाटा से भी धन प्राप्त हुआ। टाटा ने भारत की गरीबी के कारणों के अध्ययन हेतु एक चेयर लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स में स्थापित की थी। गांधी जी ने मोक्ष का पारंपरिक अर्थ भी बदला। जन्म-मरण बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष हासिल करने को उन्होंने अपना ध्येय नहीं बनाया। दरिद्र की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना।‘दान को हिंदू धर्म में मानव के सवरत्तम गुणों में माना गया है। अलबरूनी लिखता है कि हिंदू धर्म में यह अनिवार्य है कि प्रतिदिन जितना अधिक संभव हो सके दान दें। अलबरूनी के अलावा अन्य विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि धन और संपत्ति की प्रचुरता के बावजूद भारतीय त्यागमय जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। महाभारत में सेवा कार्य के लिए संपूर्ण आय का एक तिहाई हिस्सा द्यय करने की हिदायत है। 1धर्मग्रंथों में त्याग के साथ भोग की बात कही गई है। जरूरतमंद को दान देना और मानव सेवा ही ईश्वर पूजा है मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना भर ईश्वर पूजा नहीं है। विवेकानंद और टैगोर ने भी गरीबों की सेवा को ईश्वर भक्ति का समानार्थी कहा है। विवेकानंद का कहना था कि सच्ची ईश्वर उपासना वह है कि हम स्वयं को मानव जाति की सेवा में लगा दें। जब हमारा पड़ोसी भूखा मरता है तो मंदिर में भीड़ लगाने का कोई अर्थ नहीं। उनके अनुसार, ‘‘मेरे जीवन का परम लक्ष्य उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है जो दुःखी विधवाओं के आंसू पोछने में असमर्थ है, जो अनाथ बच्चों को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। वास्तविक पूजा निर्धन

और दरिद्रों की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। जिन लोगों को दो जुन भोजन भी नहीं मिलता उनसे ईश्वर की चर्चा कैसे की जाए? उनके लिए तो रोटी ही ईश्वर है। अर्थ ही आध्यात्म है। भूख और बेरोजगार के सामने ईश्वर एक ही रूप में प्रकट होने का साहस कर सकता है और वह है काम और भोजन के रूप में।’ 1हालांकि कुछेक भारतीय पूंजीपति समाज सेवा में सक्रिय हुए हैं और उन्होंने कई उल्लेखनीय काम भी किए हैं, लेकिन यह समय की मांग है कि भारत में भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स जैसे फाउंडेशन स्थापित हों और विशाल संपदा अर्जित करने वाले लोग आधी हिस्सा न सही, कुछ हिस्सा उन कार्यों में खर्च करें जिनसे गरीबी दूर करने में मदद मिले। यह समय की मांग है कि परोपकार की परंपरा को पुष्ट किया जाए और साथ ही उसे एक नई दिशा और ध्येय भी दिया जाए। गैर बराबरी को दूर करने के ठोस प्रयास इसलिए होने चाहिए, क्योंकि विषमता के दुष्प्रभाव से धनी भी बच नहीं सकते। जिन्हें विदेशी संस्थाओं और ईसाई मिशनरियों के सेवा भाव के तौर-तरीकों पर आपत्ति है उनकी तो यह जिम्मेदारी बनती है कि निर्धनता और विषमता को दूर करने का काम करने वाली भारतीय संस्थाएं स्थापित हों। यह कहीं परोपकार की पुरानी परंपरा के क्षीण होने का परिणाम तो नहीं कि अपने देश में धार्मिक स्थलों का निर्माण तो खूब होता है, लेकिन अच्छे स्कूल और अस्पताल कम ही बनते हैं। (लेखक जेएनयू में ग्रीक चेयर प्रोफेसर रहे हैं)

चुनाव पूर्व हिंसा और सियासी दमन में फंसा बांग्लादेश

अदालत ने हालांकि उन्हें रिमांड पर भेज दिया, मगर मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और उन्हें अस्पताल ले जाने व गुरुवार तक उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा। मंगलवार की देर रात तक सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया था। बांग्लादेश में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं। हो सकता है कि आलम के बहाने कट्टरपंथी खास संदेश देना चाह रहे हों, मगर बांग्लादेश के लोग अपनी आजादी को गंभीरता से लेते हैं। पिछले हफ्ते का घटनाक्रम बताता है कि बांग्लादेश 1971 के अपने आदर्शों से कितना दूर

चला गया है। मुक्ति आंदोलन के आखिरी दिनों में, पाकिस्तानी सेना ने नए मुल्क को हानि पहुंचाने के लिए दर्जनों नागरिकों और बुद्धिजीवियों को मार दिया था। ढाका के रेयर बाजार में उनकी याद में बने स्मारक पर असद चौधरी की एक पंक्ति है, जो आने वाली पीढ़ियों से एक प्रासंगिक सवाल पूछती है- तोमादेर जा बलार छिलो, बोलचे की ता बांग्लादेश? (जो आप कहना चाह रहे थे, क्या वह बांग्लादेश कहता है?) आज उन बलिदानियों के पास देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी के लिए भी कई सवाल जरूर होंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिजीटल जमा और खर्च पर है आयकर विभाग की नजर

बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग आपके हर जमा और खर्च पर डिजीटल नजर रखेगा। इससे कम छापेमारी में ज्यादा टैक्स चोरी पकड़ना संभव हो सकेगा। विभाग ने टैक्स स्कूटनी का जाल तकनीक के सहारे इतना फैला लिया है कि रिटर्न दाखिल करने के पहले ही

व्यक्ति की जमा-खर्च का लेखा-जोखा सिस्टम में पहुंच जाता है। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग इस साल टैक्स स्कूटनी में कमी करेगा। पिछले साल के एक प्रतिशत के मुकाबले केवल 0.35 फीसदी मामलों में स्कूटनी होगी। सूत्रों की मानें तो विभाग अब इस नीति पर चल रहा है कि करदाता अगर पूरी ईमानदारी से पैसा कमाते और खर्च करते हैं तो अब आयकर विभाग उनके रिटर्न की स्कुटनी नहीं करेगा। इसका फायदा यह होगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद विभाग की तरफ से नोटिस आने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। साथ ही छाप पड़ने का खतरा भी कम होगा। आयकर विभाग के नियम

पिछली सरकारों ने एथेनॉल कार्यक्रम को नहीं लिया गंभीरता से, अब बचेंगे 12 हजार करोड़

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार साल में एथेनॉल का उत्पादन तीन गुना करने का लक्ष्य तय किया है और कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से जहां किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकेगी, बल्कि सरकार के तेल आयात बिल में भी 12,000 करोड़ रुपए की कमी लाई जा सकेगी। पीएम मोदी ने वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पर हुए एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को गंभीरता से नहीं लेने के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार उहराया और कहा, ‘वायपेथी सरकार के दौरान



एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी लेकिन पिछली सरकारों ने इस प्रोग्राम को गंभीरता से नहीं लिया था। अब हम अगले साल में 450 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। नतीजतन इंपोर्ट के मद में देश के 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।' भारत अपनी 80 फीसदी तेल की जरूरतों को इंपोर्ट के माध्यम से पूरा करता है। भारत क़ुड इंपोर्ट बिल को घटाने के लिए रिन्यूएबल स्रोतों के साथ ही बिजली के इस्तेमाल के अलावा बायोफ्यूल्स को प्रोत्साहन देने पर काम कर रहा है। मोदी ने कहा कि देश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 12 बायोपयूल

चलाते नजर आएंगे। उन्होंने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कांस्ट की तुलना में डेढ़ गुना करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की तारीफ की। इस अवसर पर उन्होंने प्रोजेक्टक्स के लिए ली जाने वाली एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस में तेजी के लिए एक वेब पोर्टल ‘परिवेश’ भी लॉन्च किया और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, 2018 का अनावरण भी किया।

ग्रोसरी कारोबार में उतरी फिलपकार्ट बिगबास्केट-अमेज़ॉन को मिलेगी टक्कर



बिजनेस डेस्क। भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फिलपकार्ट ने ग्रोसरी कारोबार में कदम रख दिया है। कंपनी ने सुपरमार्ट नाम से ग्रोसरी कारोबार शुरू किया है। कंपनी

फिलपकार्ट ने ई-कॉमर्स के लिए ग्रोसरी को चुना है। फिलपकार्ट के ग्रॉसरी हेड मनीष कुमार ने कहा, ग्रॉसरी खरीदते वक्त लोग अधिक से अधिक बचत करना चाहते हैं क्योंकि इसकी खरीदारी बार-बार करनी पड़ती है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बिजनेस में कंपनी कितना पैसा लगाने जा रही है। बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने हाल ही में अमेरिकी खुदरा क्षेत्र की दिग्गज वालमार्ट के फिलपकार्ट की 77 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सोदा करीब 16 अरब डॉलर का है।

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष में सरकार को अंतरिम लाभांश का विकल्प अभी खुला है। इस बारे में फैसला इसी साल आगे हो सकता है। आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने आज यह बात कही। रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने कल जून, 2018 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए 50,000 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान करने का फैसला किया था। रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष जुलाई से जून होता है। लाभांश के वितरण को स्पष्ट करते हुए गर्ग ने कहा, ‘‘आप साल समाप्त होने के बाद लाभांश देते हैं। रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष 30



जून को समाप्त होता है। अब वे खातों को अंतिम रूप दे रहे हैं और उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया है। 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश मिला। 40,000 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में आएंगे। यह पूछे जाने पर

क्या अंतरिम लाभांश की गुंजाइश है,।

गर्ग ने कहा कि यह विकल्प खुला हुआ है। गर्ग ने कहा, ‘‘पिछले साल की तरह इस वर्ष भी अंतरिम लाभांश आ सकता है। इसकी समीक्षा संभवतः दिसंबर में हो सकती है।’’

जुलाई में 8फीसद बढ़ी वाहन बिक्री, कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 30फीसद का उछाल

नई दिल्ली। घरेलू पैसोंजर वाहनों की बिक्री में 2.71 फीसद की गिरावट देखी गई है। जुलाई महीने में कार कंपनियों ने 2,90,960 यूनिट्स की बिक्री की है, जबकि जुलाई 2017 में यह आंकड़ा 2,99,066 कारों का रहा था। यह जानकारी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) ने दी है। टू व्हीलर्स और कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में हुई जोरदार बढ़ोतरी की वजह से जुलाई में कुल वाहन बिक्री में 8

प्रतिशत का इजाफा देखने को मिला है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के दौरान देश में कुल वाहन बिक्री 22,44,875 गाड़ियों की रही है जबकि पिछले साल जुलाई में 20,79,204 वाहनों की बिक्री दर्ज की गई थी। कुल वाहन बिक्री में सबसे अधिक हिस्सेदारी टू व्हीलर्स और पैसेंजर वाहनों की होती है। जुलाई के बिक्री आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि हर 1.19 सेकेंड में देश में 1 गाड़ी बिकी है।



पिछले साल इस दौरान 2,13,591 टू व्हीलर्स का एक्सपोर्ट हुआ था। कमर्शियल गाड़ियों की बात करें तो स्ट्रूकू के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई के दौरान घरेलू मार्केट में कुल 76497 कमर्शियल गाड़ियां बिकी हैं।

रेरा लागू होने से घरों के पजेशन में 33 फीसदी की बढ़ोतरी: रिपोर्ट

नई दिल्ली। रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) लागू होने से घरों की डिलीवरी में 33 फीसदी इजाफा हुआ। नौ प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी से जून के बीच बिल्डरों ने 1 लाख 93 हजार 61 फ्लैट्स का पजेशन दिया। पिछले साल इन महीनों के दौरान यह संख्या 1 लाख 44 हजार 654 यूनिट थी। रियल्टी पोर्टल प्रॉपटाइगर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 के आखिर तक करीब 8.6 लाख घर ग्राहकों को सौंपे जाने हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और पुणे शहरों में प्रॉपटाइगर ने सर्वे किया। नोएडा में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे को भी शामिल किया गया। इसी तरह मुंबई में नवी मुंबई, ठाणे और गुरुग्राम में भिवाड़ी, धारुहेड़ा और सोहना को भी शामिल किया। इस साल जून तक अहमदाबाद में 13,380 और बेंगलुरु में 28,279 घर ग्राहकों को सौंपे गए। गुरुग्राम में 24,677 और हैदराबाद में 11,887 कुल कोलकाता में 8,314 घरों का पजेशन दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेरा लागू होने क बाद बिल्डर्स नई स्कीम लॉन्च करने की बजाय पुराने प्रोजेक्ट पूरे करने पर फोकस कर रहे हैं, ताकि पेनल्टी न लगे। रेरा की वजह से घरों का पजेशन समय पर मिलने लगा है। यह इंडस्ट्री के लिए अच्छा साबित होगा। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले फेस्टिवल सीजन में घरों की बिक्री में भी इजाफा हो सकता है।

सेबी को फोन कॉल टैप करने का अधिकार देने की सिफारिश

मुंबई। भारतीय प्रतिष्ठिति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) की एक समिति ने सुझाव दिया है कि भेदिया कारोबार और धोखाधड़ी के दूसरे तरीकों से निपटने के लिए बाजार नियामक को टेलीफोन तथा दूसरे संचार माध्यमों को टैप करने का अधिकार मांगना चाहिए। सेबी के पास अभी कॉल रिकॉर्ड का व्योरा मांगने का अधिकार है। अगर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता है तो सेबी को कॉल सुनने का भी अधिकार मिल जाएगा। निष्पक्ष बाजार आचरण के बारे में पूर्व विधि संचय टी के विश्वनाथन की अगुआई वाली इस समिति ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसे आज सार्वजनिक किया गया। समिति का कहना है कि सेबी को

एडवाइजर्स के संस्थापक और सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक संदीप पारेख ने कहा, ‘आप वित्तीय नियामकों को इस तरह का अधिकार नहीं दे सकते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है।’ समिति ने यह सिफारिश ऐसे वक्त की है जब निजता को लेकर देश में चर्चा गरम है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में कहा था कि निजता मौलिक अधिकार है। समिति ने बेनामी खातों, भेदिया कारोबार और धोखाधड़ी के दूसरे तरीकों से निपटने के लिए भी सुझाव दिए हैं। धोखाधड़ी के मामले से बेहतर ढंग से निपटने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव की सिफारिश की गई है। समिति का कहना है कि धोखाधड़ी के नियम केवल

15 रुपए प्रति किलो की छूट के साथ, 34.88 लाख टन तुअर, चना, मसूर, मूंग और उड़द जारी करने की पेशकश की फैसला राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 12 महीने के लिए है पर यदि 34.88 लाख टन का स्टॉक इससे पहले खत्म हो जाता है तो योजना वहीं खत्म कर दी जाएगी। कानून और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,

सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,237 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह फैसला राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को गोदामों के लिए दाल उपलब्ध कराने के अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में दालों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। सूर्य/केंद्रशासित प्रदेश अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि

मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) में दालों का उपयोग करेंगे। देश में पिछले दो वर्षों से दालहनों के उत्पादन के नए रिकार्ड बन रहे हैं। मूल्य समर्थन योजना के तहत केंद्र ने खरीफ 2017 और रबी 2018 विष्णुण सत्र के दौरान दालों की रिकॉर्ड खरीददारी की है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत 45.43 लाख टन दालों की रिकॉर्ड खरीद की गई है। इसमें कहा गया है कि आने वाले खरीफ सत्र में, दालों का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि इसके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण मूल्य समर्थन योजना के तहत अतिरिक्त खरीद की आवश्यकता होगी।



बॉश का मुनाफा पहली तिमाही में 42प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। वाहन कलपुर्जे बनाने वाली दिग्गज बॉश लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा 30 जून को समाप्त तिमाही में 42.42 प्रतिशत उछल कर 430.98 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में लाभ 302.61 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही में उसकी परिचालन से आय 3,212.15 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2,830.44 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने कहा कि एक जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही में परिचालन से आय की तुलना पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के आंकड़े से नहीं जा सकती है। कंपनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घरेलू बिक्री में 21.7 प्रतिशत और निर्यात में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उसका वाहन समाधान (मोबिलिटी सॉल्यूशंस) कारोबार 20.5 प्रतिशत बढ़ा है। ऊर्जा और बिजली उपकरण समेत अन्य कारोबारी क्षेत्र में 48.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान, उसका कुल खर्च 2498.16 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,677.89 करोड़ रुपए हो गया है। बॉश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौमित्र भट्टरायर्च ने कहा कि इस वर्ष वाहन उद्योग में कंपनी ने घरेलू और वैश्विक स्तर दोनों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि हम पूंजीगत खर्च, शोध एवं विकास पर अधिक व्यय और नए बाजार स्थापित करने में निवेश करना जारी

एसबीआई को 4876 करोड़ रुपए का घाटा

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में एसबीआई को 4,876 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में एसबीआई को 2,005.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में एसबीआई की ब्याज आय 23.8 फीसदी बढ़कर 21,798 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2018 की पहली तिमाही में एसबीआई की ब्याज आय 17,606 करोड़ रुपए रही थी। हालांकि जून तिमाही के दौरान बैंक के फंसे हुए कर्ज (एनपीए) में कमी देखने को मिली है, एसबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जून तिमाही में उसका ग्रांस एनपीए 2,12839.92 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, इससे पहले मार्च तिमाही में बैंक का ग्रांस एनपीए 223427.46 करोड़ रुपए था।

मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना होगा महंगा, 40फीसदी तक बढ़ेंगे टिकट के दाम!

बिजनेस डेस्क। अगर आप अक्सर मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाते रहते हैं तो जल्द ही आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। मल्टीप्लेक्स में अगर खाने-पीने का सामान ले जाने की इजाजत मिल जाती है तो आपको पहले के मुकाबले 20-40 फीसदी तक अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मल्टीप्लेक्स में फूड व बेवरेज ले जाने की इजाजत को लेकर बाम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। खबरों के मुताबिक अगर फूड व बेवरेज को मल्टीप्लेक्स में ले जाने की इजाजत मिल जाती है तो मल्टीप्लेक्स को फूड व बेवरेज के कारोबार से मिलने वाले रेवन्यू में कमी आएगी, जिसकी भरपाई मल्टीप्लेक्स वाले निश्चित रूप से टिकट के दाम बढ़ाकर करेंगे। यानी कि अभी अगर सिनेमा के टिकट के लिए आप 200 रुपए चुकाते हैं तो आपको 240-280 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। पीवीआर जैसे बड़े मल्टीप्लेक्स के कुल कारोबार में फूड व बेवरेज की हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक है। चालू वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में पीवीआर ने 684.36 करोड़ रुपए का कारोबार किया और इनमें फूड एवं बेवरेज की हिस्सेदारी 202.71करोड़ रुपए की थी। सूत्रों के अनुसार कई ऐसे दर्शक होते हैं तो मल्टीप्लेक्स में फूड व बेवरेज के महंगे होने की वजह से सिर्फ सिनेमा देखते हैं, कुछ खाते-पीते नहीं हैं। लेकिन अगर फूड व बेवरेज ले जाने की इजाजत मिलती है तो निश्चित रूप से टिकट के दाम बढ़ेंगे जिसकी कीमत सभी दर्शकों को चुकानी होगी।

जेट एयरवेज के शेयरों में भारी गिरावट

मुम्बई। जेट एयरवेज के संस्थापक चेयरमैन नरेश गोयल ने कहा कि उनके शेयरधारकों को इस समय पैसा गंवाना पड़ा है जिसकी वजह से वह अपने को ‘दोषी और शर्मिंद’ महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्तीय संकट से जूझ रही इस निजी एयरलाइन कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। यह एक संपूर्ण सेवा विमानन कंपनी है। इसका शेयर 2 जुलाई के बाद से 12 प्रतिशत टूट चुका है। आज कारोबार के दौरान यह 52 सप्ताह के निचले स्तर 286.95 रुपए पर आ गया। कंपनी का शेयर 5 जनवरी 2018 को 52 सप्ताह के उच्चस्तर 883.65 रुपए पर पहुंचा था। उस समय के बाद से आज यह 67.5 प्रतिशत नीचे है। एयरलाइन की वित्तीय सेहत और कर्मचारियों के वेतन में कटौती के प्रस्ताव की चिंता के बीच जेट एयरवेज के चेयरमैन ने कहा कि सार्वजनिक धारणा सुधारने तथा नकारात्मक प्रचार को रोकने के लिए एक नई समिति गठित की जाएगी। गोयल ने कहा कि नई कार्यकारी समिति के जरिए कंपनी के बारे में सभी धारणाओं को सुधारा जाएगा।

कड़ोदरा में नौ साल की मासूम के साथ बलात्कार

आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के दुकान व बाइक में लगाई आग

सूरत। कड़ोदरा स्थित मस्जिद के पास वाहन रिपेरिंग करने वाले युवक पे 9 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की जमकर धुनाई करने के बाद उसकी दुकान व बाइक में आग लगा दी। पीड़िता को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

मिली जानकारी के अनुसार कड़ोदरा नगर स्थित निलम होटल के सामने गाड़ी रिपेरिंग का काम करने वाला राजू रामजी सुथार निवासी

चलथाण के तुलसी पार्क सोसायटी प्रवासी और अलवर राजस्थान का मूल निवासी है। उसके बगल में स्थित मदीना मस्जिद में नवाज अता के लिए मुस्लिम समाज के लोग अंदर थे। वह मौका पाकर वह एक नौ वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया अऔर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह दुष्कर्म के बाद बाहर निकल गया और बालिका जमीन पर गड़द ते- राड ते बाहर निकली। बालिका को लहुलुहान हाल में देख स्थानीय लोग औरोपी राजू सुथार को पकड़ लिया और जमकर धुनाई

करने लगे। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की दुकान और बाइक में आग लगा दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कड़ोदरा पुलिस आरोपी को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंची। बालिका को तुरंत संजोवनी हास्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से बालिका को सूरत स्थित न्यू सिविल अस्पताल में ले जाया गया। बालिका की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। अस्पताल में पीड़िता की माता सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा है।

मंदिर के पुजारी के पैर में गोली मारकर 50 हजार की लूट

सूरत। जिले के कुंवरदा स्थित गंगा ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारी को गोली मारकर तीन शख्स रु. 50 हजार की लूट चलाकर फरार हो गए। देर रात हुई इस घटना की पुलिस ने जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सूरत जिले की मांगरोल तहसील के कुंवरदा गांव की सोमा स्थित गंगा ओमकारेश्वर मंदिर में शंकरगिरी मोलेश्वर पुजारी हैं। सावन महीने के दौरान उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से वीरेन्द्रकुमार प्रेमनारायण पांडेय हर साल कुंवरदा गांव आते हैं। रात्रि के दौरान दोनों पुजारी मंदिर परिसर में बने कमरे में रहते हैं। बीती रात करीब 10 बजे लोगों के जाने के बाद दोनों पुजारी मंदिर में अकेले थे। शंकरगिरी

अपने कमरे में सो रहे थे, जबकि वीरेन्द्रकुमार मंदिर परिसर में रखे बैच पर जाप कर रहे थे। उस वक्त मंदिर परिसर की दीवार फांदकर तीन शख्स घुस आए। एक शख्स ने वीरेन्द्र पांडेय की आंख मिर्च पाउडर झाँक दिया और उनकी कनपटी पर बंदूक तान दी। मिर्च पाउडर झाँके जाने से वीरेन्द्र की आंखों में जलन होने लगी और वह चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर कमरे में सो रहे शंकरगिरी बाहर निकल आए। उनके कमरे से बाहर आते ही तीन में से एक शख्स ने शंकरगिरी की जांघ में गोली मार दी।

डीसीबी पुलिस ने गोड़ादरा में पकड़ा नकली दारू बनाने का कारखाना

दारू बनाने के केमिकल, ब्रांडेड दारू कंपनी के लेबल के साथ एक को पकड़ा

सूरत। डीसीबी पुलिस गोड़ादरा में एक नकली दारू बनाने के कारखाने को पकड़ा और नकली दारू बनाने के केमिकल सहित कुल 17, 320 रु का सामान के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, और एक के खिलाफ वारेन्ट जारी किया गया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि गोड़ादरा सुपर सिनेमा के पास आस्तिक नगर के बाजूमे शिवनगर सोसायटी की दुकान नंद 01 महावीर नगर सोसायटी

प्लॉट नं. 45 के पहले माले के कमरे में रेड मारी। रेड के दौरान पुलिस ने दिनों जगहों से डुप्लिकेट दारू बनाने का सामान मिला। तीनों स्थानों पर से पुलिस केमिकल अन्य साधनों, डुप्लिकेट दारू मिला कुल 17, 320 रु. का सामान अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी कैलाश नानुराम आरम्भीया को साई पैलेस कल्पना नगर मराठी स्कूल के सामने गोड़ादरा से पकड़ा, तथा अन्य आरोपी नारायण कलाकने वोन्टेड जाहीर करके आगे कि कार्यवाही शुरू की है।

अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी

सरखेज, नारायणपुर और शाहीबाग में अतिक्रमण दुर

अहमदाबाद । महानगरपालिका एवं शहर पुलिस की ओर से शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान आज शुक्रवार के दिन भी जारी रहा। शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की गई। जिसके चलते सैकड़ों अतिक्रमण दुर किये गए। मनापा व पुलिस का मेगा अभियान को लेकर सनसनी फैल गई है। गैरकानूनी अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या को दुर करने के तहत शहर में एक के बाद एक इलाकों में पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से मेगा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध सेड दुर किये जा रहे हैं। अतिक्रमण दुर करने की कार्रवाई अगले दिनों में भी जारी रहने के संकेत मिल चुके हैं।

पिछले कुछ दिन से जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान आज भी जारी रहा। जि

सके चलते शहर के सरखेज, नारायणपुरा, शाहीबाग समेत के इलाकों में अतिक्रमण दुर किये गए। आरटीओ तंत्र की ओर से भी घाटलोडिया, भुयंगदेव, थलतेज समेत के इलाकों में सात से अधिक स्कूलों में जांच की गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से आज भी आक्रमक कार्रवाई की गई। गैरकानूनी सेड, क्रोस चोल, लारी गल्ले हटाए गए। म्युनिसिपल कमिशनर विजय नहेरा के स्पष्ट आदेश के बाद यह कार्रवाई चल रही है। तंत्र की ओर से की जा रही कार्रवाई को लोगों की तरफ से भी अच्छा सहकार मिल रहा है। उत्तर जोन के एक दो जगहों को छोड़कर कॉर्पोरेशन की टीम को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। आज मध्य जोन के एस्टेट विभाग की टीम ने शाहीबाग, असारवा वार्ड में स्थित

विठ्ठलनगर चार रास्ते से लेकर एफएसएल चार रास्ता, रामेश्वर चार रास्ता तक कार्रवाई की। चार किलोमीटर लंबे रोड पर अतिक्रमण को दुर किया गया। पश्चिम जोन में नारायणपुर आईसी विस्तार में कार्रवाई की गई। पूर्व जोन में सरदार पटेल रींग रोड पर के दास्तान फर्म से लेकर रामोल सर्कल तक कार्रवाई हुई। नई पश्चिम जोन में आज लगातार पांचवे दिन भी कार्रवाई हुई। सरखेज चौकडी से लेकर शांतिपुरी सर्कल तक कार्रवाई की गई। आरटीओ के ३० से अधिक इन्स्पेक्टरों की मदद से पश्चिमी इलाकों में कार्रवाई का दौर जारी रहा। सात से अधिक स्कूलों में आरटीओ नियम के बारे में कड़ी जांच की गई। जिसके तहत स्कूल वान रीक्सा और स्कूल वान ड्राइवरो की पूछताछ की गई।

युवाओं को रोजगार के लिए साढ़े सात व १० लाख की सहायता

आरक्षण से वंचित वर्ग के लिए गुजरात सरकार की नई घोषणा

महिलाओं को चार फिसदी ब्याज पर लोन देने की घोषणा : स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करनेवाले छात्रों को एक साल में २० हजार की सहायता मिलेगी

अहमदाबाद । गुजरात सरकार ने आज मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आरक्षण से वंचित वर्ग के लिए कई घोषणाए की हैं। आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। यह लाभ सालाना तीन लाख रुपये कमानेवाले परिवारों को ही मिल सकेगा। मुख्यमंत्री आवास पर उच्चस्तरीय बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने घोषणाए की हैं। उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने गांधीनगर में पत्रकारों को बताया कि गुजरात गैर आरक्षित शैक्षणिक व आर्थिक निगम के गठन की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ५८ जातियां ऐसी हैं, जो गैरआरक्षित वर्ग से आती हैं। इस वर्ग के

छात्र-छात्राओं को दसवीं व १२वीं में ६० फीसदी से अधिक अंक हासिल करने पर उच्च शिक्षा के लिए ४ फीसद ब्याज दर पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए साढ़े सात व दस लाख रुपये तक की सहायता ५ फीसद ब्याज पर तथा महिलाओं को ४ फीसद ब्याज पर लोन दिया जाएगा। सरकार यूपीएससी व जेपीएससी व रेलवे भर्ती व बैंक की स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वालों को एक साल में २० हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है। आज गुजरात सरकार ने जो योजनाए घोषित की हैं उसमें शैक्षणिक अभ्यास योजना, विदेश अभ्यास लोन सहाय योजना, भोजन बिल सहाय योजना, ट्युशन सहाय योजना, गुजकेंट

परीक्षा के लिए कोचींग सहायता योजना, स्पर्धात्मक परीक्षा के लिए तालीम सहाय योजना, स्वरोजगार लक्ष्य योजना, स्नातक, डॉक्टर, वकील, टेकनिकल स्नातक के लिए ब्याज सहाय योजना शामिल है। सभी योजना इसी साल से लागू की जाएगी। सभी योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। गुरुवार शाम को सीएम आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री विजय रुपानी, उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल, वरिष्ठ मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुडासमा, प्रदीप सिंह जाडेजा व मुख्य सचिव डॉ.एन. के सिंह व आयोग के अध्यक्ष वी एच घोडासरा आदि शामिल थे। इसमें बताया गया कि गुजरात में ५८ जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता

। जिनमें एक करोड़ लोग आते हैं। नौकरी, शिक्षा में इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा इसलिए अन्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा करते हुए चालू शैक्षणिक सत्र से ही छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए नीतिन पटेल ने बताया कि सामाजिक समरसता, देश की संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए हरेक वर्ग व समुदाय की प्रगति के लिए राज्य सरकार की ओर से दो तीन साल से अनेक योज नाएं लाए। संविधान में आरक्षण का प्रावधान को रखते हुए आरक्षण से वंचित अन्य वर्ग को लाभ देने के लिए महिला पुरुष व युवाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए इस आयोग का गठन किया गया है।



सूरत। गजेरा स्कूल, अमरोली रोड के पास से पुलिस ने शुक्रवार को स्कूलों बच्चों से भरी 15 वेन जब्त करी।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात करते हुए नवसारी सांसद सी.आ. पाटील, संदीप देसाई तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति।

एनआरआई हत्या केस में फरार आरोपी 14 साल बाद उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

अहमदाबाद। गुजरात एटीएस ने सूरत के एनआरआई के अपहरण और हत्या केस में पिछले 14 साल से फरार कुख्यात बंटी पांडे गिरोह के शख्स को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर सूरत पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार अप्रैल 2004 में अमेरिका से हीरा खरीदने सूरत ओ एनआरआई

राजेश भट्ट की उत्तर प्रदेश के बंटी गिरोह ने हीरा की बड़ी डील के नाम पर अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उनके परिजन से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी थी और इसके लिए राजेश भट्ट की ऑडियो क्लिप भी बनाई। बाद में राजेश भट्ट की हत्या कर उनका शव खेडा जिले के

नडियाद में चकलासी रोड के निकट फेंक दिया था। हत्या के बाद ऑडियो क्लिप के आधार पर राजेश भट्ट के अमेरिका स्थित परिवार से करोड़ों की फिरौती मांगी थी। सूरत की महीधरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया था और मामले की जांच ब्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

मणीनगर में स्या की आड़ में चल रहे सेक्स रेकेट का पर्दाफास

अहमदाबाद। शहर के मणीनगर इलाके में स्थित जवाहरचौक के निकट एक कोम्प्लेक्स में कोहीनूर स्या सेन्टर की आड़ में चलाए जा रहे सेक्स रेकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जिसके चलते पुरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मणीनगर पुलिस ने जानकारी के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्या सेन्टर पर अचानक छापेमारी की। जिसके चलते आरोपी महिला संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चार सेक्स वर्करो को भी संचालक के शिकंजे में से छुड़ाया गया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में जानने को मिला है कि आरोपी महिला संचालक

मुंबई और गुजरात में से सेक्स वर्करो को बुलाती थी और स्या सेन्टर की आड़ में गोरखधंधा चला रही थी। शहर के मणीनगर विस्तार में स्थित जवाहरचौक के निकट शिवानी एवन्यु में कोहीनूर स्या सेन्टर चल रहा था। स्या सेन्टर के नाम पर देह व्यापार किया जा रहा था। जानकारी के आधार पर पुलिस ने फर्जी कस्टमर भेजकर पहले जानकारी इकठ्ठा की। जानकारी पक्की निकलने पर छापेमारी की गई। कोहीनूर स्या सेन्टर में चल रहे सेक्स रेकेट को पकड़ना सरल नहीं था। स्या सेन्टर के संचालक बिल्कीश बानु मुल मुंबई की है और पिछले कुछ

सालो से अहमदाबाद में रहती थी और कोहिनूर स्या सेन्टर चला रही थी। स्या में कोई भी कस्टमर थेरापी लेने के लिए पहुंचता था तब कस्टमर के पास से मसाज के रुपये लिये जाते थे। इसके बाद सेक्स वर्कर मसाज के लिए ग्राहकों को कमरे में ले जाती थी और सेक्स की ओफर की जाती थी। कस्टमर यदी मान जाए तो सेक्स वर्कर को रुपये दिए जाते थे। योजनापूर्वक यह रेकेट चलाया जा रहा था। चार युवतियों को सिकंजे से बचाया गया है। जिसमें से दो युवतियां मुंबई की और दो गुजरात की होने की जानकारी मिली है।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाइन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्प्लेक्स नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।